भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1947

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

.....

तमिलनाडु में पीएमकेएसवाई

1947. श्री डी. एम. कथीर आनंदः

डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियनः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में जल भंडारण में सुधार, बाढ़ को कम करने और सिंचाई क्षमता बढ़ाने हेतु जल निकायों और पानी के टैंकों के पुनरुद्धार हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत कोई धनराशि स्वीकृत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या तमिलनाडु विशेषकर वेल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला सेवा का नेटवर्क चलाने और जनता के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्र जल परीक्षण किट का प्रावधान करने हेतु कोई धनराशि आवंटित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु में जल स्रोतों की संवहनीयता बढ़ाने के लिए कोई जल-भूवैज्ञानिक परियोजनाएं शुरू की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास तमिलनाडु में विकास और अनुसंधान कार्यकलाप के अलावा जल के स्रोतों की सुरक्षित खोज के लिए ब्लॉक-वार भूजल मानचित्र, भूजल खोज और जल पुनर्भरण से संबंधित अध्ययन तैयार करने के लिए कोई निधि है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): जी, हाँ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर खेत को पानी (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी) के अंतर्गत, भारत सरकार ने जल भंडारण क्षमता में सुधार और सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से तमिलनाडु सहित राज्यों को जल स्रोतों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान की है।

तमिलनाडु में 645 जल निकायों वाले कुल नौ क्लस्टरों को पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत केंद्रीय वित्तपोषण के लिए मंजूरी दी गई थी। 31 मार्च 2025 तक तमिलनाडु सरकार को केंद्रीय सहायता के रूप में 156.19 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान वित्तीय वर्ष में पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए 41.91 करोड़ रुपए की समग्र मंजूरी प्रदान की गई है।

(ख): जल जीवन मिशन (जेजेएम) के संचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इस योजना के अंतर्गत अपनी वार्षिक आवंटन के अधिकतम 2% भाग का उपयोग जल गुणवत्ता निगरानी और निरीक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएंडएस) गतिविधियों के लिए कर सकते हैं। इसमें जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की सेवा का संचालन और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने हेतु फील्ड वाटर टेस्टिंग किट्स की उपलब्धता शामिल है।

तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2024–25 के दौरान जेजेएम के अंतर्गत तमिलनाडु को 39.85 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिनमें से 56.60 लाख रुपए वेल्लोर जिले में जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला सेवा के लिए अनुमोदित किए गए हैं। इसके अतिरिकत, प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीण जल स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) के सदस्यों को एफटीके प्रशिक्षण प्रदान करने और फील्ड वाटर टेस्टिंग किट (एफटीके) की खरीद के लिए 4.55 लाख रुपए अनुमोदित किए गए हैं।

(ग) और (घ): भारत सरकार ने तमिलनाडु में जल संसाधनों की स्थिरता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से कई हाइड्रो-भूवैज्ञानिक अध्ययन और कार्यकलाप की शुरूआत की हैं। भारत सरकार द्वारा तमिलनाडु में संसाधनों की स्थिरता के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं:

पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने तमिलनाडु जल आपूर्ति और जल निकासी बोर्ड (डीडब्लयूएडी बोर्ड) को 198.92 लाख रुपए की लागत से तमिलनाडु 'भूजल संभावनाओं का मानचित्रण (हाइड्रो-भूगोलिक मानचित्र)' परियोजना को मंजूरी दी थी। एनआरएससी के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रारंभ में, टोपोशीट–वार (220) भूजल संभावनाओं के मानचित्र तैयार किए गए और वर्ष 2012 के दौरान 1:50,000 पैमाने पर पूर्ण किए गए। क्षेत्र के सुलभ संदर्भ हेतु, ब्लॉक-वार एचजीएम मानचित्र तैयार किए गए और उन्हें सभी आरडब्ल्यूएस प्रभागों और टीडब्ल्यूएडी बोर्ड के सर्कल कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग, नगर प्रशासन, टाउन पंचायत, कृषि इंजीनियरिंग विभाग, जल संसाधन विभाग, केंद्रीय भूजल बोर्ड और सभी जिला कलेक्टरों को सौंपा गया।

पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने तमिलनाडु के लिए "भूजल संभावनाओं का मानचित्रण (एचजीएम नक्शे)" को स्वीकृति दी थी, जिसमें ब्लॉक-वार नक्शे बनाए गए हैं। एचजीएम एटलस की मदद से विभिन्न पुनर्भरण संरचनाएं जैसे चेक डैम, पर्कोलेशन तालाब और रिचार्ज शाफ्ट बनाए गए हैं ताकि जल स्रोतों की संवहनीयता सुनिश्चित हो सके।

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने देश के पूरे मानचित्रण योग्य क्षेत्र, लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूयूआईएम) परियोजना को भी पूरा किया है, जिसमें तमिलनाडु के 1,05,742 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। जलभृत मानचित्र और प्रबंधन योजनाओं

को तैयार किया गया है और कार्यान्वयन हेतु तमिलनाडु सहित संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया गया है।

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से कृत्रिम भूजल पुनर्भरण मास्टर प्लान 2020 तैयार किया है, जो देश के विभिन्न भौगोलिक संरचनाओं के लिए विभिन्न ढांचों को दर्शाने वाली एक व्यापक योजना है, जिसमें तमिलनाडु भी शामिल है। कृत्रिम भूजल पुनर्भरण मास्टर प्लान 2020 को तमिलनाडु सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किया गया और इसे प्रत्येक राज्य में एक जिले में राज्य योजनाओं के सहयोग से इसे कार्यान्वित किया किया जा रहा है। मास्टर प्लान के अनुसार, तमिलनाडु में लगभग 88,000 कृत्रिम वर्षा जल संचयन संरचनाओं और छत पर वर्षा जल संचयन की योजना बनाई गई है, जिससे 959 मिलियन क्यूबिक मीटर अतिरिक्त पानी के संचयन की परिकल्पना की गई है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, केंद्रीय क्षेत्र की योजना, भूमिगत जल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएमआर) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, तमिलनाडु राज्य सहित, पूरे देश में भूजल संसाधनों के अन्वेषण, निगरानी, मूल्यांकन और प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जाता है, जिसमें जलभृत मानचित्र तैयार करना, भूजल अन्वेषण और पुनर्भरण अध्ययन शामिल हैं। इन सभी गतिविधियों के लिए व्यय की पूर्ति जीडब्ल्यूएमआर योजना के कुल आवंटन से की जाती है।

*****